



ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्म-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-2.25

Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025

Page No.- 112-121

©2025 Gyanvividha

<https://journal.gyanvividha.com>

मनोज काक

(शिक्षक), राजकीय बालिका उच्च
माध्यमिक विद्यालय, बिरामी-पाली
(राजस्थान).

Corresponding Author :

मनोज काक

(शिक्षक), राजकीय बालिका उच्च
माध्यमिक विद्यालय, बिरामी-पाली
(राजस्थान).

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के संदर्भ में शिक्षक से अपेक्षाएँ और उनकी व्यावहारिक चुनौतियाँ

सारांश : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) शिक्षा को समावेशी, लचीला, बहुआयामी और कौशल-आधारित बनाने पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षक को परिवर्तन का मुख्य वाहक माना गया है। नीति उनसे नवाचारपूर्ण, मूल्य-आधारित, बहुभाषिक और डिजिटल शिक्षण अपनाने की अपेक्षा करती है। शोध में पाया गया कि अधिकांश शिक्षक नीति के उद्देश्यों से सहमत हैं, पर संसाधनों की कमी, डिजिटल विभाजन, प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और प्रशासनिक कार्यभार बाधक हैं। सफल क्रियान्वयन हेतु समुदाय, पंचायत व विद्यालय प्रशासन की सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना और सतत मूल्यांकन आवश्यक है, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक सशक्त और भविष्य उन्मुख बन सके।

बीज शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षण, मूल्य-आधारित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निरंतर व्यावसायिक विकास, संसाधन कमी, डिजिटल विभाजन, शिक्षक प्रशिक्षण, 360 डिग्री मूल्यांकन, नीति-व्यवहार अंतर, शैक्षिक नवाचार, सामुदायिक सहभागिता।

प्रस्तावना (Introduction) : शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास की आधारशिला है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा न केवल ज्ञानार्जन का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रमुख साधन भी है। समय और परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता होती है, ताकि यह नई पीढ़ी को वैश्विक चुनौतियों से निपटने योग्य बना सके। इसी परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) लागू की, जो 34 वर्षों बाद आई एक व्यापक और दूर-

दर्शी नीति है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, बहुआयामी, समावेशी और कौशल-आधारित बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक समग्र नीति है। यह पूर्व की नीतियों की तुलना में अधिक समावेशी, सीखने-केंद्रित और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की संकल्पना के अनुरूप ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संतुलित विकास करना है।

इस नीति में शिक्षा के सभी स्तरों—पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक—के लिए सुधारात्मक एवं नवाचारपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनमें 5+3+3+4 संरचना का निर्धारण, मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बनाना, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास का समावेश, डिजिटल शिक्षा और मिश्रित शिक्षण पर बल, मूल्य-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण, तथा शोध एवं नवाचार को बढ़ावा जैसे बिंदु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। NEP-2020 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह शिक्षा को केवल परीक्षा और अंक तक सीमित नहीं रखती, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और जीवन कौशल विकसित करने पर बल देती है।

किसी भी शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वाले मानव संसाधन कितने कुशल, प्रशिक्षित और प्रेरित हैं। इस दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय है। शिक्षक केवल ज्ञान का संवाहक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। NEP-2020 में शिक्षक को “राष्ट्र निर्माता” की संज्ञा दी गई है। शिक्षक विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल पाठ्य सामग्री का ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि मूल्य,

दृष्टिकोण और व्यवहार भी आकार देता है। शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा संबंध शिक्षक की योग्यता, प्रशिक्षण और समर्पण से होता है। डिजिटल युग में शिक्षक को 21वीं सदी के कौशलों—जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षण, मिश्रित अधिगम और मूल्य-आधारित शिक्षण पद्धतियों—में दक्ष होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक से अनेक अपेक्षाएँ स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं। प्रथम, उनसे अपेक्षा की गई है कि वे पारंपरिक व्याख्यान पद्धति के साथ-साथ परियोजना-आधारित, समस्या-समाधान आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण को अपनाएँ। द्वितीय, वे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन विकसित करें और उन्हें प्रश्न पूछने, तर्क करने और नये समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। तृतीय, वे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देते हुए बहुभाषी दक्षता विकसित करें और शिक्षा को स्थानीय संदर्भों से जोड़ें। चतुर्थ, वे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन तथा मिश्रित शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करें। पंचम, वे अपने सतत व्यावसायिक विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करें और नये पाठ्यक्रम एवं शिक्षण रणनीतियों से अद्यतन रहें। षष्ठ, वे समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, पिछड़े वर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए संवेदनशील एवं सहायक वातावरण बनाएं। अंत में, वे मूल्य-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करें ताकि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण की भावना, सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और वैश्विक नागरिकता की चेतना विकसित हो।

यद्यपि NEP-2020 में शिक्षक से जुड़ी अपेक्षाएँ व्यवहारिक और दूरदर्शी हैं, किंतु इनके सफल क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं। नीतिगत दस्तावेज़ और कक्षा-कक्ष की वास्तविकताओं में अंतर है, जिसे पाटना आवश्यक है।

अनेक शिक्षक अभी भी नई शिक्षण तकनीकों और डिजिटल साधनों के प्रयोग में पूरी तरह दक्ष नहीं हैं। अनेक विद्यालयों में तकनीकी, भौतिक और मानव संसाधनों की कमी है। सतत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता भी एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षक पर प्रशासनिक कार्यों का अत्यधिक बोझ, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताएँ और पाठ्यक्रमीय दबाव भी नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं।

इन परिस्थितियों में इस विषय पर शोध अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है। यह शोध नीति-अपेक्षा और व्यावहारिक स्थिति के बीच के अंतर को उजागर करेगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने शिक्षक नई शिक्षण तकनीकों में दक्ष हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने प्रभावी हैं और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन एवं सहयोग की आवश्यकता है। इस शोध के निष्कर्ष न केवल नीति निर्माताओं को सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करेंगे, बल्कि शिक्षक-केंद्रित सुधारों को भी गति देंगे। साथ ही, यह शोध भविष्य की शैक्षिक नीतियों और कार्ययोजनाओं के लिए साक्ष्य-आधारित दिशा प्रदान करेगा।

अतः यह कहा जा सकता है कि NEP-2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसमें शिक्षक को परिवर्तन के मुख्य वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीति में शिक्षक के लिए जो अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं, उनका उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण का समग्र विकास करना है। किंतु इन अपेक्षाओं को व्यवहार में उतारने के लिए शिक्षक को उपयुक्त प्रशिक्षण, संसाधन और सहयोग की आवश्यकता होगी। इस शोध की प्रासंगिकता इसी तथ्य में निहित है कि यह शिक्षक अपेक्षाओं और उनकी चुनौतियों का वास्तविक परिदृश्य उजागर करेगा तथा ठोस और व्यावहारिक सुझाव प्रदान करेगा। इससे न केवल NEP-2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त, समावेशी और भविष्य उन्मुख बनाया

जा सकेगा।

2. शोध प्रश्न (Research Questions)

- NEP 2020 के अनुसार शिक्षक से किन-किन अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है?
- शिक्षक की भूमिका में नीति से उत्पन्न नए बदलाव और जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
- शिक्षकों को नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में किन-किन व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
- शिक्षक की पेशेवर विकास प्रक्रिया में किन सुधारों की आवश्यकता है?
- इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

साहित्य समीक्षा (Literature Review) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित साहित्य में सरकारी दस्तावेज़, आयोगों की रिपोर्टें, शोध लेख, नीति विश्लेषण और विभिन्न संस्थागत अध्ययन शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा जारी NEP-2020 का आधिकारिक दस्तावेज़ इस विषय का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधारात्मक उपायों, शिक्षक की भूमिका, डिजिटल शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षण और मूल्य-आधारित शिक्षा के प्रावधान विस्तार से वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त, ड्राफ्ट NEP-2019 और उससे पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 के संशोधन भी संदर्भित किए जाते हैं, ताकि नीतिगत परिवर्तनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे NCERT, NIEPA और NCTE ने भी नीति के क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या सुधार पर कई महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किए हैं।

शिक्षक के पेशेवर विकास और भूमिका पर साहित्य विशेष रूप से समृद्ध है। Day (1999) और Villegas-Reimers (2003) ने अपने शोध में यह दर्शाया है कि सतत पेशेवर विकास (Continuous Professional Development) शिक्षक की

दक्षता, प्रेरणा और शिक्षण नवाचारों को अपनाने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। भारतीय संदर्भ में, NCTE की 2018 की रिपोर्ट और NCERT द्वारा 2021 में जारी शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि NEP-2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और नवाचारी शिक्षण-पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। साथ ही, Guskey (2002) का निष्कर्ष यह बताता है कि शिक्षक के पेशेवर विकास का वास्तविक प्रभाव तब ही दिखता है जब प्रशिक्षण कक्षा-कक्ष की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली सामान्य बाधाओं और समस्याओं पर अनेक अध्ययनों ने प्रकाश डाला है। Fullan (2007) ने शिक्षा सुधार के संदर्भ में यह तर्क दिया कि नीति क्रियान्वयन में शिक्षक की सहभागिता और प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। भारतीय संदर्भ में, Kumar (2017) और Singh & Yadav (2021) ने यह पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, डिजिटल अवसंरचना की अनुपलब्धता, बड़े कक्षा आकार, और शिक्षक पर प्रशासनिक कार्यों का बोझ नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। NEP-2020 के प्रारंभिक क्रियान्वयन चरण में भी विभिन्न राज्य सरकारों की प्रगति रिपोर्टों में यही चुनौतियाँ बार-बार सामने आई हैं।

डिजिटल शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा और समावेशी शिक्षण पर भी पर्याप्त शोध उपलब्ध है। OECD (2015) और UNESCO (2020) की रिपोर्टें डिजिटल साक्षरता को 21वीं सदी का एक अनिवार्य कौशल मानती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में Dikshit & Sharma (2021) ने COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, और डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता प्रमुख मुद्दे रहे। बहुभाषिक शिक्षा पर Cummins

(2000) और Mohanty (2009) के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा न केवल भाषाई दक्षता को बढ़ाती है, बल्कि सीखने की गति और संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होती है। समावेशी शिक्षण पर Ainscow (2013) और Sharma (2018) के शोध यह बताते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल करने के लिए शिक्षक की दृष्टि, संसाधन और सहयोगी ढांचा अत्यंत आवश्यक है।

वैश्विक संदर्भ में शिक्षा नीतियों और शिक्षक की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन भी उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। Finnish National Education Policy में शिक्षक को अत्यधिक स्वायत्तता और पेशेवर सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप फ़िनलैंड की शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान पर है। इसी प्रकार, सिंगापुर की शिक्षा नीति सतत शिक्षक प्रशिक्षण, मेंटरिंग और तकनीकी समावेशन पर बल देती है। OECD के TALIS सर्वे (2018) के निष्कर्ष बताते हैं कि जिन देशों में शिक्षक को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की उपलब्धि दोनों बेहतर होती हैं। इन वैश्विक उदाहरणों की तुलना भारतीय NEP-2020 के प्रावधानों से करने पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक के पेशेवर विकास, डिजिटल दक्षता और नीति क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक ढाँचा आवश्यक है।

सारांशतः, उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि NEP-2020 का सफल क्रियान्वयन शिक्षक की तैयारी, पेशेवर विकास, संसाधन उपलब्धता और नीतिगत समर्थन पर निर्भर है। डिजिटल शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षण और समावेशी दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख घटक बन चुके हैं, जिन्हें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका के साथ जोड़ा जाना अनिवार्य है। साथ ही, वैश्विक संदर्भों से मिली सीख यह दर्शाती है कि यदि शिक्षक को उपयुक्त सहयोग,

प्रशिक्षण और स्वायत्तता प्रदान की जाए, तो नीति के लक्ष्यों को व्यवहार में लाना संभव है।

शोध उद्देश्य :

- NEP 2020 में शिक्षक से अपेक्षाओं को समझना।
- नीति के अनुसार शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण करना।
- शिक्षकों को व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण और विकास की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सुधार सुझाव देना।

अनुसंधान की पद्धति (Research Methodology) : इस शोध में वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) पद्धति का संयोजन अपनाया गया। डेटा संग्रह हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक डेटा के लिए चयनित क्षेत्र में प्रश्नावली, अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार एवं फोकस ग्रुप चर्चा (FGD) का प्रयोग किया गया। नमूना चयन हेतु Purposive Sampling एवं Stratified Random Sampling तकनीकों का प्रयोग किया गया। द्वितीयक डेटा सरकारी रिपोर्ट, जनगणना, शोध लेख, पुस्तकें एवं ऑनलाइन स्रोतों से संकलित किया गया। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों एवं गुणात्मक व्याख्या दोनों के माध्यम से किया गया, जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक एवं प्रमाणिक बन सके।

व्याख्या एवं विश्लेषण

1: पृष्ठभूमि : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह नीति 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक समावेशी, लचीली, बहुभाषिक और बहुआयामी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। इसमें शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन

तक सीमित न रखकर, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों के संवर्धन पर बल दिया गया है। इस बदलाव में शिक्षक को परिवर्तन के मुख्य वाहक के रूप में देखा गया है, जो कक्षा-कक्ष से लेकर व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य तक प्रभाव डाल सकते हैं।

भारत में शिक्षकों की भूमिका ऐतिहासिक रूप से केवल पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सामाजिक दिशा और सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहक भी रहे हैं। NEP-2020 में यह दृष्टिकोण और मजबूत किया गया है, जिससे शिक्षक अब केवल "ज्ञानदाता" नहीं, बल्कि "सीखने के सहायक" (Facilitators of Learning) बन गए हैं। यह बदलाव न केवल उनकी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाता है, बल्कि उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को भी पुनर्परिभाषित करता है।

नीति में विशेष रूप से बहुभाषिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक शिक्षा, और समावेशी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया गया है। इसके लिए शिक्षक को नई तकनीकों का उपयोग, नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग और विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन करना होगा।

हालाँकि, नीति के सफल क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी हैं, जैसे— संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, शिक्षक-छात्र अनुपात की समस्या, और प्रशासनिक कार्यभार। यह शोध इन्हीं पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास करेगा, ताकि नीति और व्यवहार के बीच की खाई को कम करने के उपाय सुझाए जा सकें।

इस शोध का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह NEP-2020 के क्रियान्वयन के वास्तविक परिदृश्य को उजागर करेगा। इसमें शिक्षक की भूमिका, उनके सामने आने वाली बाधाएँ, प्रशिक्षण और विकास की स्थिति, तथा सुधार की संभावनाएँ स्पष्ट होंगी। यह न केवल शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के लिए,

बल्कि शिक्षक समुदाय के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक से अपेक्षाएँ

: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए व्यापक सुधारों का स्वाका प्रस्तुत किया है। इस नीति के केंद्र में शिक्षक हैं, जिन्हें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। शिक्षक से अपेक्षाओं को केवल पाठ्यक्रम के संप्रेषक तक सीमित न रखकर, उन्हें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के मार्गदर्शक, मूल्य संवाहक और नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में परिभाषित किया गया है।

1. नवीन शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना : NEP-2020 के अंतर्गत शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि वे पारंपरिक रटंत-आधारित शिक्षा पद्धति से हटकर गतिविधि-आधारित, कौशल-आधारित और अनुभव-जन्य शिक्षण को बढ़ावा दें। शिक्षक को ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप क्लासरूम, प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग जैसी पद्धतियों को अपनाकर विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने की आवश्यकता है।

2. मूल्य एवं नैतिक शिक्षा का समावेश : NEP-2020 के अनुसार, शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम भी है। शिक्षक से अपेक्षा है कि वे अपने व्यवहार, संवाद और शिक्षण सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, करुणा, अनुशासन, पर्यावरण-जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का संचार करें।

3. भाषाई लचीलापन और बहुभाषी शिक्षण : NEP-2020 बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करती है, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के प्रयोग पर बल देती है। शिक्षक से अपेक्षा है कि वे भाषा की विविधता का सम्मान करें, विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष बनाएं और भाषाई समावेशिता को बढ़ावा दें।

4. समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का

संवर्धन : शिक्षक से यह अपेक्षा है कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN), सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग (SEDGs) और विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। इसके लिए शिक्षण विधियों में लचीलापन, भिन्नकृत शिक्षण (Differentiated Instruction) और सहायक तकनीकों (Assistive Technologies) का प्रयोग आवश्यक है।

5. प्रौद्योगिकी का एकीकृत उपयोग : डिजिटल युग में शिक्षक को ICT (Information and Communication Technology) का कुशल उपयोगकर्ता होना चाहिए। NEP-2020 में अपेक्षित है कि शिक्षक डिजिटल संसाधनों, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाएं।

6. निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development) :

NEP-2020 के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना चाहिए। शिक्षक से अपेक्षा है कि वे नए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धतियों, विषयगत शोध और शिक्षण नवाचारों से स्वयं को अद्यतन रखें।

7. 360-डिग्री मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका : शिक्षक को केवल परीक्षा-आधारित मूल्यांकन तक सीमित न रहते हुए, समग्र मूल्यांकन (Holistic Assessment) में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसमें विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक (Cognitive), सामाजिक-भावनात्मक (Socio-emotional) और व्यवहारिक (Behavioral) क्षमताओं का आकलन शामिल है।

8. विद्यालय समुदाय के साथ सहयोग : शिक्षक से अपेक्षा है कि वे अभिभावकों, स्थानीय समुदाय और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूल-समुदाय सहभागिता को मजबूत करें। इससे शिक्षा प्रक्रिया अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनती है।

9. अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा : NEP-2020

शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास, शैक्षिक प्रयोगों और स्थानीय संदर्भ आधारित नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और संदर्भ-संवेदनशील बने।

3. शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में शिक्षक को केवल ज्ञान प्रदाता (Knowledge Provider) के रूप में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के सहायक (Facilitator), मार्गदर्शक (Mentor) और आदर्श (Role Model) के रूप में देखा गया है। शिक्षक की भूमिका अब कक्षा तक सीमित न होकर विद्यालय, समुदाय और व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य तक विस्तारित हो गई है।

3.1 शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएँ

1. शिक्षण-अधिगम का सुगमकर्ता

विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking), समस्या समाधान कौशल (Problem-Solving Skills) और रचनात्मकता (Creativity) का विकास करना।

विविध शिक्षण विधियों जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम आदि का प्रयोग।

2. समानता और समावेशन के संवाहक :

सभी पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों को समान अवसर प्रदान करना।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षण रणनीतियों का उपयोग।

3. नवाचार एवं तकनीकी प्रयोगकर्ता : डिजिटल उपकरणों, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संसाधनों का उपयोग।

स्थानीय संदर्भ और छात्र की रुचियों के अनुसार शिक्षण सामग्री का अनुकूलन।

4. मूल्य एवं जीवन कौशल विकास के मार्गदर्शक : विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, सहानुभूति, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का संवर्धन।

21वीं सदी के कौशल जैसे संचार, नेतृत्व, समय

प्रबंधन और टीम वर्क का विकास।

5. समुदाय और अभिभावक सहभागिता के संवाहक

विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य।

अभिभावकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना।

3.2 शिक्षक की जिम्मेदारियाँ

1. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी :

पाठ्यक्रम को NEP 2020 के लचीले, बहुविषयक और कौशल-आधारित स्वरूप के अनुरूप लागू करना। 360-डिग्री समग्र मूल्यांकन पद्धति अपनाना।

2. व्यावसायिक विकास : Continuous Professional Development (CPD) कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी।

शोध, नवाचार और नई शिक्षण रणनीतियों को अपनाना।

3. नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

पेशेवर नैतिकता का पालन करना।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान देना।

4. पर्यावरणीय एवं सामाजिक चेतना का प्रसार :

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति जागरूकता फैलाना।

पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों का संचालन।

संक्षेप में, NEP 2020 में शिक्षक को नेता, प्रेरक, नवोन्मेषक और सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में देखा गया है। उनकी भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को सकारात्मक दिशा देने और समाज के भविष्य को आकार देने तक विस्तृत है।

4. शिक्षक को सामना करनी पड़ने वाली व्यावहारिक चुनौतियाँ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) ने शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली के केंद्र में रखते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचार-आधारित शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है। परंतु, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों को अनेक व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ

केवल विद्यालय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, प्रशासनिक, तकनीकी और व्यक्तिगत स्तर पर भी मौजूद रहती हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं—

1. बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी
 - कई विद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, स्मार्ट-क्लासरूम और डिजिटल संसाधनों की कमी रहती है।
 - ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का अभाव शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
2. अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात
 - कक्षाओं में अत्यधिक विद्यार्थियों के कारण व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो जाता है।
 - NEP-2020 के अनुसार, आदर्श छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में।
3. डिजिटल विभाजन (Digital Divide)
 - ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा लागू करने में कई शिक्षकों और विद्यार्थियों को तकनीकी उपकरणों और इंटरनेट की कमी का सामना करना पड़ता है।
 - वरिष्ठ शिक्षकों के लिए नई तकनीकों को अपनाना समय और प्रशिक्षण की मांग करता है।
4. निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development) की चुनौतियाँ
 - NEP-2020 ने शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण पर बल दिया है, परंतु प्रशिक्षण के अवसरों का समान रूप से उपलब्ध न होना और समय की कमी बड़ी समस्या है।
 - कार्यभार अधिक होने के कारण शिक्षक प्रशिक्षण में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते।
5. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता
 - विविध पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, जिनके अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाना चुनौतीपूर्ण है।
 - भाषाई विविधता और स्थानीय संदर्भों को शिक्षण में समाहित करना समय और कौशल दोनों मांगता है।

6. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में बदलाव की जटिलता
 - NEP-2020 के तहत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धतियों में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं।
 - नई प्रणाली को समझना और लागू करना शिक्षकों के लिए समय और प्रयास का विषय है।
 7. प्रशासनिक कार्यभार
 - शिक्षण के अलावा प्रशासनिक और गैर-शैक्षिक कार्य (जैसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी, सर्वेक्षण) शिक्षकों के समय और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं।
 8. सामुदायिक सहभागिता की कमी
 - विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वय का अभाव कई बार शिक्षण-प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कम करता है।
 - अभिभावकों की शिक्षा में सीमित भागीदारी एक चुनौती है।
 9. मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रेरणा की कमी
 - परीक्षा परिणामों का दबाव, प्रशासनिक अपेक्षाएँ और समाज की आलोचना शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
 - आर्थिक असमानताएँ और प्रमोशन में देरी भी उत्साह को कम कर सकती हैं।
 10. नीति और ज़मीनी स्तर पर अंतर
 - NEP-2020 में जो आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत है, उसका वास्तविक रूपांतरण जमीन पर ढांचा, संसाधन और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी के कारण कठिन हो जाता है।
- अध्याय 6: शिक्षकों के अनुभव और दृष्टिकोण – सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार का सामूहिक विश्लेषण
- इस अध्ययन में 100 शिक्षकों (60 सरकारी विद्यालय एवं 40 निजी विद्यालय) को शामिल किया गया, जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक सम्मिलित थे। डेटा संग्रह ऑनलाइन प्रश्नावली और अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। इस अध्याय में प्राप्त तथ्यों का मात्रात्मक (Quantitative) और गुणात्मक (Qualitative) दोनों दृष्टिकोणों से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

6.1 शिक्षकों की जागरूकता :

सारणी संख्या:01

क्र.स.	संकेतक	आँकड़ा (%)
1	NEP 2020 के बारे में पूर्ण जागरूकता	78%
2	सीमित जानकारी	22%
3	गतिविधि/प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण	65%
4	नियमित ICT टूल्स का उपयोग	58%
5	पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर	42%
6	50 घंटे से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले	46%
7	संसाधन व छात्र-शिक्षक अनुपात को मुख्य चुनौती मानने वाले	72%

इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षक नीति से परिचित हैं और शिक्षण में नवाचार अपना रहे हैं, लेकिन तकनीकी अवसंरचना और प्रशिक्षण में अंतर प्रमुख बाधा है।

6.2 गुणात्मक विश्लेषण (Qualitative Analysis)
साक्षात्कार से निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आए—
शिक्षण में नवाचार – एक वरिष्ठ उच्च माध्यमिक शिक्षक ने कहा: "NEP 2020 ने हमें विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों और प्रोजेक्ट्स से जोड़ने का अवसर दिया है, जिससे वे अधिक उत्साहित रहते हैं।"

तकनीकी चुनौतियाँ – ग्रामीण प्राथमिक शिक्षिका का कहना था: "प्रशिक्षण तो मिला, लेकिन इंटरनेट और उपकरणों की कमी के कारण ICT का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे।"

विद्यार्थियों की सहभागिता – कई शिक्षकों ने बताया कि नई पद्धतियों से विद्यार्थियों की कक्षा में सक्रियता और सीखने की इच्छा बढ़ी है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता – कुछ शिक्षकों ने प्रशिक्षण को अधिक स्कूल-केंद्रित और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भाषा और मूल्य शिक्षा – मातृभाषा आधारित शिक्षण को सकारात्मक बताया गया, परंतु स्थानीय भाषा में सामग्री की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई।

6.3 सामूहिक निष्कर्ष (Integrated Findings)

सकारात्मक दृष्टिकोण – अधिकांश शिक्षक NEP 2020 के लक्ष्यों और दिशा को सही मानते हैं।

आंशिक क्रियान्वयन – नीति का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में अधिक दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन-आधारित बाधाएँ हैं।

तकनीकी अंतर – डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ा है, परंतु सभी शिक्षकों में तकनीकी दक्षता समान नहीं है।
प्रशिक्षण की अपर्याप्तता – प्रशिक्षण का समय, आवृत्ति और गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।
समावेशी शिक्षा में बाधाएँ – दिव्यांग और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय 7: नीति के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सुझाव एवं निष्कर्ष

7.1 सुधार हेतु सुझाव : विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम (School Health and Wellness Programme) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित ठोस एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

पंचायत एवं स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी
ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एवं निगरानी में शामिल किया जाए।

पंचायत निधियों से स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए।

शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का संयुक्त प्रशिक्षण

शिक्षक-स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के लिए इंटरएक्टिव एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएं।

प्रशिक्षण में जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिक उपचार के विषय भी शामिल किए जाएं।

समुदाय एवं अभिभावक सहभागिता :

नियमित हेल्थ कैंप और जागरूकता अभियान आयोजित कर समुदाय को जोड़ा जाए।

अभिभावकों को बच्चों की पोषण स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी प्रगति की जानकारी दी जाए।

स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढीकरण :

विद्यालयों में प्रथम उपचार केंद्र, स्वच्छ पेयजल, और सुरक्षित शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

बालिकाओं के लिए अलग एवं सुरक्षित सैनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध हों।

निगरानी और मूल्यांकन तंत्र :

रियल-टाइम डाटा एकत्र करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए।

मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए।

NEP 2020 के अनुरूप समन्वित दृष्टिकोण :

विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम को समग्र शिक्षा एवं होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए।

स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य जीवन कौशल विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए।

7.2 निष्कर्ष : विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत के तहत, बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब पंचायत, स्कूल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अभिभावक और समुदाय सभी की सक्रिय सहभागिता हो। NEP 2020 के प्रावधानों के अनुरूप यह कार्यक्रम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी प्रोत्साहित कर सकता है। अतः, मजबूत नीति, सुदृढ़ अवसंरचना, प्रशिक्षित मानव संसाधन, और सतत निगरानी इस कार्यक्रम की सफलता की कुंजी हैं।

संदर्भ :

1. कुमार, एस., एवं वर्मा, आर. (2021)। शिक्षक का व्यावसायिक विकास: एनईपी 2020 के लक्ष्यों की ओर एक मार्ग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, 9(3), 87-95। (पृ. 13)
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2021)। एनईपी क्रियान्वयन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल। एनसीईआरटी प्रकाशन। (पृ. 13)
3. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। (2021)। एनईपी क्रियान्वयन हेतु शिक्षक क्षमता निर्माण पर नीति सार। नीपा। (पृ. 13)
4. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। (2020)। एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु दिशानिर्देश। एनसीटीई। (पृ. 13)
5. भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय। (पृ. 13)
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय। (2019)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। भारत सरकार। (पृ. 13)
7. वर्मा, अ., एवं सिंह, म. (2022)। एनईपी 2020 के संदर्भ में डिजिटल साक्षरता और मिश्रित शिक्षण। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 13(4), 112-120। (पृ. 13)
8. विश्व बैंक। (2021)। भारत में शिक्षा का रूपांतरण: एनईपी 2020 के अनुरूप। विश्व बैंक समूह। (पृ. 13)
9. श्रीवास्तव, पी., एवं गुप्ता, आर. (2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका: अवसर एवं चुनौतियाँ। इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेटिव रिसर्च, 10(2), 45-56। (पृ. 13)
10. सिंह, पी., एवं कौर, एच. (2022)। बहुभाषिक शिक्षा और समावेशी कक्षाएँ: एनईपी 2020 के प्रकाश में एक अध्ययन। कॉन्टेम्प러리 एजुकेशन डायलॉग, 19(1), 56-73। (पृ. 13)



ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-2.25

Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025

Page No.- 122-131

©2025 Gyanvividha

<https://journal.gyanvividha.com>

**RAUT NILESHKUMAR
KAILASHBHAI**

Research Scholar,
Department of Commerce,
Veer Narmad South Gujarat
University, Surat, Gujarat,
India.

Corresponding Author :

**RAUT NILESHKUMAR
KAILASHBHAI**

Research Scholar,
Department of Commerce,
Veer Narmad South Gujarat
University, Surat, Gujarat,
India.

A Study on Unemployment Trends Over the Last Decade in India

Abstract : Unemployment has remained one of the most pressing challenges for the global economy, and India, despite being one of the fastest-growing economies, has not been immune to its fluctuations. Over the last decade, unemployment in India has experienced periods of stability, sharp increases during the COVID-19 pandemic, and uneven recovery in recent years. This paper explores unemployment trends from 2010 to 2025 with a specific focus on their implications for commerce, business growth, consumer demand, and economic policy. The study emphasizes the intersection between unemployment and commerce by analyzing how joblessness influences trade, market expansion, entrepreneurship, and financial performance. Through secondary data analysis, literature review, and comparative insights, this research identifies structural challenges, highlights the gaps in job creation, and proposes sustainable solutions for reducing unemployment while fostering inclusive economic development. The findings suggest that despite government initiatives such as "Skill India," "Startup India," and MGNREGA, unemployment remains high among youth and graduates, calling for deeper reforms in education, vocational training, and labour market policies.

Keywords : Unemployment, Reforms, India, Commerce, Economy.

Introduction : Unemployment is not merely an economic indicator; it is a multidimensional issue that affects business growth, consumer purchasing power, social stability, and national development. In the context of commerce, unemployment has a direct bearing on demand, supply, and overall market efficiency. A high unemployment rate leads to reduced disposable income, declining consumer confidence, and weaker business performance. Conversely, effective employment generation fuels economic expansion, promotes entrepreneurship, and enhances overall trade activity.

Globally, unemployment has seen fluctuations driven by technological shifts, globalization, and policy changes. The last decade (2010–2025) has been particularly eventful. Before 2020, India's unemployment rate remained relatively stable at around 5–5.6%. However, the COVID-19 pandemic disrupted this trajectory, causing unemployment to soar to unprecedented levels, touching nearly 26% in April 2020 according to CMIE estimates. The years 2021–2025 saw gradual recovery, though unemployment remained elevated at 7–8% in 2023–2024 before showing signs of improvement in 2025.

From a commerce perspective, unemployment has significant implica-

tions. For instance, persistent unemployment among educated youth indicates a mismatch between academic learning and market requirements. This mismatch not only affects individual livelihoods but also weakens the entrepreneurial ecosystem, reduces innovation, strains social welfare systems. Furthermore, unemployment influences consumer demand, investment flows, and even government revenue collection through taxes, thereby directly affecting the functioning of the commerce sector.

This research paper explores unemployment trends in India over the last decade, with a dual lens—economic and commerce-related. It seeks to answer the following key questions:

1. What have been the major unemployment trends in India between 2010 and 2025?
2. What structural and cyclical factors have contributed to unemployment?
3. How does unemployment affect commerce, trade, and consumer behavior?
4. What policies and interventions have been implemented, and how effective have they been?
5. What strategies can be adopted to reduce unemployment while strengthening India's commercial ecosystem?

By addressing these questions, the paper aims to contribute to both academic literature and policy discourse

on employment, commerce, and sustainable economic development.

Literature Review : Unemployment has been widely studied as a macroeconomic problem, but its linkages with commerce and business development have gained more attention in recent decades. Several researchers have analyzed how unemployment influences not only economic growth but also consumption, investment, and market structures.

Unemployment and Economic Growth : Okun's Law (Okun, 1962) established an inverse relationship between unemployment and economic growth, suggesting that persistent unemployment reduces productive capacity and weakens GDP. More recent studies (Verick, 2021; World Bank, 2023) reinforce that economies with high unemployment struggle with reduced competitiveness and declining household demand.

Youth and Graduate Unemployment : According to Kannan and Raveendran (2019), India has faced a paradox of "jobless growth," where GDP expanded without proportionate job creation. Studies by Mehrotra (2020) indicate that graduate unemployment in India remains particularly high due to a mismatch between education systems and labour market requirements. Youth unemployment is seen as not only an economic problem but also a social challenge, creating risks of unrest and inequality.

Unemployment and Commerce Sector :

Scholars have emphasized how unemployment affects commerce directly. According to Prasad and Singh (2018), high unemployment reduces consumer purchasing power, thereby lowering demand for goods and services. Similarly, Kumar (2021) noted that unemployment among youth has slowed the growth of retail trade and e-commerce in India. On the other hand, the gig economy has emerged as an alternative form of employment, as discussed by Abraham et al. (2022).

Government Initiatives and Employment Generation : Studies by NITI Aayog (2021) and Sharma (2022) have evaluated schemes like MGNREGA, Startup India, and Skill India. While these have created some employment opportunities, structural challenges—such as informality, underemployment, and automation—continue to undermine their effectiveness. Research by ILO (2023) highlights that the informal sector absorbs a large share of the unemployed, but jobs remain precarious and low-paying.

Comparative Insights : International comparisons show that unemployment in India behaves differently from developed nations. While European countries often face cyclical unemployment due to economic downturns, India faces structural unemployment due to education-job mismatches (ILO, 2020). A study by Gupta and Thomas (2022) indicates that unlike China, where

industrial expansion absorbed labour, India's service-led growth has not created sufficient employment opportunities.

In summary, the literature suggests that while unemployment in India has macroeconomic causes, its impact is most visible in commerce through reduced demand, slower business expansion, and weaker consumer confidence. However, limited research has integrated unemployment analysis with commerce, leaving scope for deeper exploration.

Objectives of the Study : The primary objective of this research is to analyze unemployment trends in India over the last decade (2010–2025) from a commerce perspective. Specific objectives include:

1. To examine the major trends in unemployment in India between 2010 and 2025.
2. To identify the structural, cyclical, and policy-driven factors contributing to unemployment.
3. To study the impact of unemployment on commerce, including consumer demand, trade, and business growth.
4. To assess the effectiveness of government initiatives aimed at employment generation.
5. To compare India's unemployment trends with selected global economies.
6. To suggest strategies for reducing unemployment while strengthening India's commercial ecosystem.

Research Methodology : This research adopts a descriptive and analytical approach, based primarily on secondary data.

Data Sources: Data has been collected from government reports (NSSO, Periodic Labour Force Survey, CMIE, NITI Aayog), World Bank, International Labour Organization, Reserve Bank of India, and peer-reviewed journals. Newspaper articles, industry reports, and policy briefs have also been referred to.

Nature of Data : The study focuses on macro-level unemployment data from 2010–2025. Both annual and monthly data have been considered to capture fluctuations, especially during the COVID-19 pandemic.

Scope of the Study : Covers India with limited comparative references to BRICS and global unemployment trends.

Focuses on unemployment's link with commerce, i.e., business growth, consumer behavior, and trade.

Analyzes government interventions and their impact on employment generation.

Analytical Framework : Trend Analysis for unemployment rates across the decade.

Comparative Analysis with select economies.

Thematic Analysis for understanding policy initiatives and their effectiveness.

The study is limited by its reliance on secondary data and may not capture informal/unreported employment comprehensively. However, the insights

derived provide a strong foundation for policy recommendations.

Analysis of Unemployment Trends (2010–2025) : Unemployment trends in India over the last decade reflect both structural challenges and cyclical shocks.

Between 2010 and 2019, the unemployment rate remained relatively stable, fluctuating around 5– 5.6%. However, the COVID-19 pandemic (2020) caused a sudden spike, followed by a gradual but uneven recovery.

Table 1: Unemployment Rate in India (2010–2025)

YEAR	Unemployment Rate (%)	Key Observation
2010	5.60	Stable baseline
2011	5.50	Minor decline
2012	5.45	Stable
2013	5.41	Stable
2014	5.44	Pre-reform stability
2015	5.45	Similar to 2014
2016	5.50	Demonetization shock
2017	5.33	Slight decline
2018	5.36	Stable
2019	5.36	Pre-covid situation
2020	8.00 (26% peak in April)	Covid lockdown crisis
2021	5.98	Recovery begins
2022	7.33	Urban-Rural divide visible
2023	8.00	High unemployment persists
2024	7.80	Signs of stabilization
2025	7.90 (Feb)	CMIE estimates
2025	5.10 (Apr)	PLFS monthly survey

Source: CMIE, PLFS, World Bank, ILO (compiled by author)

Factors Affecting Unemployment (Commerce & Economic Viewpoint)

1. Economic Growth vs Job Creation : India experienced strong GDP growth (6–7%) pre-COVID, but much of it was “jobless growth”. Growth driven by IT and services did not absorb large sections of the workforce, particularly low-skilled labour.

2. Skill Mismatch : A major factor is the

mismatch between education and market needs. Despite producing millions of graduates annually, many lack vocational skills. This results in high graduate unemployment (42% in 2023).

3. Technological Disruption : Automation, AI, and digitalization have replaced certain low-skilled jobs, especially in manufacturing, banking, and retail

commerce. While creating new digital jobs, they often require skills that unemployed youth do not possess.

4. Informal Sector Dependence : Over 80% of India's workforce is employed in the informal sector. This leads to disguised unemployment, underemployment, and lack of job security, limiting consumption capacity.

5. Pandemic Shock (2020) : COVID-19 led to massive job losses in retail, hospitality, transport, and construction. Commerce-related businesses suffered as consumer demand collapsed due to layoffs.

6. Urban-Rural Divide : Urban unemployment rose sharply during the pandemic, while rural areas relied on MGNREGA as a fallback. However, rural employment often remained low-paying and seasonal.

7. Policy and Structural Constraints : While schemes like Skill India and Startup India aimed to generate jobs, bureaucratic hurdles, lack of coordination, and weak implementation reduced their impact.

Impact of Unemployment on Commerce and Business : Unemployment is not only a social problem but also a commercial constraint. The following effects are particularly significant for the commerce sector:

1. Reduced Consumer Demand :

Unemployed individuals have limited disposable income, which lowers overall demand for goods and services. For

example, FMCG sales dipped in 2020–21 as rural demand weakened due to rising joblessness.

2. Impact on Retail & E-commerce : The growth of e-commerce relies heavily on young, urban consumers. High youth unemployment reduces purchasing power and slows retail expansion.

3. Decline in Investment : Businesses hesitate to expand when consumer demand is low, leading to a vicious cycle of weak job creation.

4. Financial Sector Stress : Unemployment increases loan defaults and reduces savings, affecting banking and financial institutions.

5. Entrepreneurship Slowdown : While some unemployed individuals turn to self-employment, lack of credit access and financial literacy limits large-scale entrepreneurship.

6. Tax Revenue Loss : Governments collect lower indirect and direct taxes when fewer people are employed, reducing public spending capacity and slowing commerce.

Sector-Wise Analysis of Unemployment in India : Unemployment impacts sectors differently. In India, the three dominant sectors—agriculture, manufacturing, and services—have shown distinct patterns.

1. Agriculture Sector : Employs nearly 42% of India's workforce* but contributes only about 16–17% to GDP.

Seasonal unemployment is widespread due to dependence on monsoon cycles.

Many agricultural workers are “disguisedly unemployed,” meaning more people work than necessary for actual output.

Despite government schemes (PM-Kisan, MSP system), agriculture remains unable to absorb surplus labour.

2. Manufacturing Sector : Considered a driver of job creation under the “Make in India” initiative.

However, manufacturing’s share in employment has stagnated at around 12–14%.

Automation and capital-intensive production processes reduced demand for labour.

COVID-19 disrupted MSMEs (micro, small, and medium enterprises), leading to factory shutdowns and layoffs.

3. Services Sector : Contributes nearly 55% to India’s GDP, but employs only 30% of the workforce.

Growth concentrated in IT, finance, and high-skilled services, leaving out semi-skilled and low-skilled workers.

Retail, tourism, and hospitality were severely hit during the pandemic, with large-scale layoffs.

Gig economy platforms (Swiggy, Zomato, Ola, Uber) absorbed some unemployed youth, but jobs are informal, low-paying, and insecure.

Table 2: Sector-Wise Employment Share in India

Sector	Employment Share (%)	GDP Contribution (%)
Agriculture	~ 42	~ 16-17
Manufacturing	~ 12-14	~ 25
Services	~ 30-32	~ 55

Source: NSSO, PLFS, RBI Reports

Government Schemes and Policy Analysis: India has launched multiple programs to address unemployment, with mixed results:

1. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

Provides 100 days of wage employment in rural areas.

Helped reduce rural distress during COVID-19 but limited to unskilled, low-wage work.

2. Skill India Mission (2015) : Aimed to train over 400 million people by 2022.

Progress has been uneven, with many

trained youth still unemployed due to lack of industry alignment.

3. Startup India & Stand-up India (2016)

Encouraged entrepreneurship by providing credit and tax benefits.

Startups created jobs, but urban-centric and limited in scale.

4. Make in India (2014) : Targeted manufacturing sector growth and job creation.

Progress hampered by slow investment and global competition.

5. Atmanirbhar Bharat (2020, COVID-19 response) : Provided credit to MSMEs and

self-reliant businesses.

Helped sustain businesses but did not significantly reduce unemployment.

6. Labour Law Reforms (2020–2021) :

Simplified labour codes to encourage business hiring.

Implementation challenges remain at state level.

Comparative International Perspective:

To contextualize India's unemployment, it is useful to compare with BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, South Africa):

Table 3: Unemployment Rate in BRICS (2024)

Country	Unemployment Rate (%)	Key Observations
India	7.8	Structural and pandemic recovery
Brazil	7.9	High cyclical unemployment
Russia	3.2	Stable, low unemployment
China	5.2	Industrial absorption
South Africa	32.0	Chronic unemployment crisis

Source: World Bank, ILO (2024)

India's unemployment is higher than China and Russia but far lower than South Africa.

Unlike Brazil (cyclical unemployment due to economic slowdown), India's problem is structural, rooted in labour–skill mismatch.

China absorbed rural labour into manufacturing, while India's services-driven growth left many behind.

Findings and Discussion:

From the analysis of unemployment trends (2010–2025), several key findings emerge:

1. Pre-COVID Stability (2010–2019) :

Unemployment remained relatively stable (~5–5.6%).

However, this stability masked structural unemployment due to skill mismatches and disguised rural unemployment.

2. COVID-19 Shock (2020): Unemployment spiked to 26% in April 2020 (short-term peak).

Retail, hospitality, manufacturing, and trade sectors saw mass layoffs.

3. Uneven Recovery (2021–2025) : Urban unemployment remained higher than rural due to disruptions in services and retail.

Youth and graduates faced persistently higher unemployment (42% of graduates unemployed in 2023).

4. Commerce-Specific Effects : Reduced consumer demand directly hit FMCG, retail, and e-commerce.

Decline in household savings and lower purchasing power slowed business expansion.

Informal gig jobs absorbed some unemployed youth but offered poor income stability.

5. Sectoral Imbalance : Agriculture remains overburdened (42% workforce, ~16% GDP).

Manufacturing failed to expand employment despite “Make in India.”

Services sector growth concentrated in IT and finance, bypassing semi-skilled workers.

6. Policy Outcomes : Schemes like MGNREGA and Atmanirbhar Bharat provided temporary relief but did not solve structural unemployment.

Skill India trained millions, but lack of demand–supply alignment limited effectiveness.

Startup India helped urban entrepreneurship but failed to scale nationwide.

7. Global Comparison : India’s unemployment is higher than China (5.2%) and Russia (3.2%), but much lower than South Africa (32%).

India’s unemployment is primarily structural, unlike Brazil (cyclical).

Conclusion : Unemployment in India over the last decade demonstrates the interplay of stability, crisis, and partial recovery. The period from 2010 to 2019 reflected a stable trend, but without sufficient job creation to match economic growth. The pandemic disrupted this balance, exposing the fragility of India’s labour market. Despite recovery efforts, unemployment continues to hover around 7–8%, with youth and educated unemployment remaining disproportion-

ately high.

From a commerce perspective, unemployment has severe implications: Lower consumer demand leads to weaker sales and slower business growth.

Reduced household incomes affect investment, credit, and financial markets. Informality and gig employment expand, but without social security or income stability.

The structural nature of unemployment in India demands more than short-term relief measures. It requires long-term reforms in education, skill alignment, industrial expansion, and entrepreneurship ecosystems.

Suggestions :

1. Strengthen Skill Development Programs
Align training with industry demand (e.g., AI, data analytics, renewable energy).

Focus on employability rather than just certification.

2. Boost Manufacturing and MSMEs :
Provide incentives for labour-intensive industries (textiles, food processing).

Support MSMEs with credit and market access to absorb local labour.

3. Formalize the Gig Economy :
Provide social security, insurance, and minimum wage protections for gig workers.

4. Encourage Rural Entrepreneurship :
Promote agribusiness, food processing, and rural startups to reduce disguised unemployment.

5. Policy Coordination :

Integrate labour reforms, industrial policy, and education policy to ensure holistic job creation.

6. Global Best Practices :

Learn from China's labour absorption into industry and Germany's vocational training model.

References :

1. Abraham, V., Sharma, R., & Kannan, G. (2022). The gig economy in India: Opportunities and challenges. *Economic & Political Weekly*, 57(21), 45–53.
2. Gupta, A., & Thomas, R. (2022). Employment patterns in India and China: A comparative perspective. *Journal of Development Studies*, 58(4), 521–540.
3. International Labour Organization (ILO). (2020). *World Employment and Social Outlook*. Geneva: ILO.
4. International Labour Organization (ILO). (2023). *Global Employment Trends Report*. Geneva: ILO.
5. Kannan, K. P., & Raveendran, G. (2019). From jobless growth to job loss growth: Gainers and losers during 2012–2018. *Economic & Political Weekly*, 54(44), 63–72.
6. Kumar, S. (2021). Unemployment and its impact on retail trade in India. *Indian Journal of Commerce & Management*, 12(3), 77–92.
7. Mehrotra, S. (2020). *India's employment crisis: Rising education, falling job opportunities*. Cambridge University Press.
8. NITI Aayog. (2021). *Employment trends in India: Challenges and opportunities*. Government of India.
9. Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. *American Statistical Association*.
10. Prasad, R., & Singh, A. (2018). Unemployment and consumption behaviour in India. *Journal of Applied Economics*, 17(2), 211–229.
11. Sharma, N. (2022). Evaluating Skill India: Successes and failures. *Journal of Policy Analysis*, 14(1), 33–49.
12. Verick, S. (2021). Unemployment dynamics in emerging markets: A comparative study. *World Bank Policy Paper Series*.
13. World Bank. (2023). *World Development Indicators*. Washington DC: World Bank.

•